दैनिक
विश्वनाथ समाचार
RNI NO. MPHIN/25/A4357
संदीप सेन (प्रधान संपादक)
मो. 9755161156
www.vishwanathsamachar.com | इंदौर, बुधवार 4 नवम्बर 2026 | वर्ष 1 | कुल पृष्ठ : 8 | DIGITAL EDITION

सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

डेवलपमेंट-इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकार किए 23 हजार 300 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास, पर्यावरण संतुलन और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्वीकृति 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए प्रदान की गई है।

स्वीकृत राशि में से सर्वाधिक 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के लिए 1,994 करोड़ 30 लाख रुपये, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये, इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए 1,107 करोड़ 6 लाख रुपये और जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के लिए 604 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यालय स्थापना, वन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन, कार्य योजना निर्माण और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन के लिए भी आवश्यक बजट मंजूर किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में वनों के संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों को नई गति मिलेगी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 9 योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करना है। मुख्यालय स्थापना और कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना योजनाओं का उद्देश्य मुख्यालय से लेकर मैदानी वनमंडलों तक प्रशासनिक नियंत्रण, वनों की सुरक्षा और अमले का प्रबंधन करना है। कार्य आयोजना का निर्माण योजना का उद्देश्य वनों के सतत व वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है, जबकि वन प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन वनकर्मियों को प्रशिक्षित एवं कार्यदक्ष बनाने के लिए है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना का उद्देश्य प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग किए जाने के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय क्षति के दुष्प्रभावों को कम करना है। इमारती लकड़ी का उत्पादन योजना का लक्ष्य काष्ठ व बांस का वैज्ञानिक विदोहन, परिवहन, विक्रय और राजस्व अर्जन है। वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान स्थापना योजना द्वारा 9 टाइगर रिजर्व एवं 10 राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण व विकास किया जाएगा।

कैबिनेट ने वनों के संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए वन विभाग के अंतर्गत संचालित 9 प्रमुख विद्यमान योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए कुल 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

भूटान का सम्मान

मोदी को समर्पित हुआ 76वां बौद्ध स्तूप



108 स्तूपों में खास पहचान, भारत-भूटान मैत्री और गेलेफू परियोजना के समर्थन को मिला आध्यात्मिक सम्मान

थिम्पू। भारत और भूटान की दोस्ती को एक विशेष आध्यात्मिक पहचान मिली है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में 108 बौद्ध स्तूपों में से 76वां स्तूप समर्पित किया है। यह समारोह 1 नवंबर को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में आयोजित हुआ। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समारोह में भाग लिया। उन्होंने भूटान के राजा के साथ स्तूप संख्या 76 की समर्पण पट्टिका का अनावरण किया और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आभार व्यक्त किया। यह सम्मान गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और भारत-भूटान संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। इस आयोजन में 108 स्तूप स्थापित किए गए।

प्रत्येक स्तूप 15 मीटर ऊंचा है और इनके निर्माण में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे भारत के लिए बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक है।

पुणे को पिंक मेट्रो की सौगात

आज मोदी करेंगे उद्घाटन

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

पुणे। शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार देने वाली मेट्रो लाइन-3 यानी पिंक लाइन का उद्घाटन आज 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो माध्यम से करेंगे। करीब 8,313 करोड़ रुपये की लागत से बना 23.2 किलोमीटर लंबा गलियारा मान से जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन तक जुड़ेगा। इससे हिंजवड़ी के आईटी केंद्र और शिवाजीनगर के बीच सफर आसान होने की उम्मीद है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि पूरी लाइन पर ट्रेनें महिला संचालक चलाएंगी। करीब 30 प्रतिशत बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने की योजना है। यात्रियों के लिए व्यावसायिक सेवाएं 4 नवंबर सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। शुरुआती चरण में 23 में से 17 स्टेशन खुलेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की करीब 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इससे शहर के कई प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों की संपर्क सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

होर्मुज में धमाके

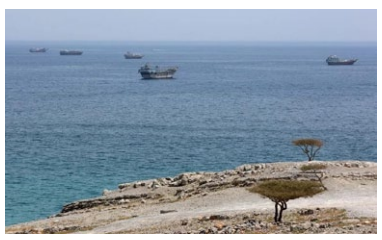
ईरान-अमेरिका आमने-सामने!

केश्म द्वीप पर सैन्य कार्रवाई की खबर, अमेरिकी ड्रोन गिराने के ईरानी दावों से बढ़ी हलचल; बातचीत के संकेतों के बीच टकराव गहराया

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

तेहरान/वॉशिंगटन। रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है।

ईरान के केश्म द्वीप पर सोमवार देर रात पांच धमाकों की खबर सामने आई। ईरानी सरकारी मीडिया ने धमाकों की सूचना दी, जबकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों में सीमित अमेरिकी



हमलों की बात कही गई है। अमेरिकी पक्ष ने इन्हें रक्षात्मक कार्रवाई बताया है। इसी बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि उसके बलों ने दो अमेरिकी एमक्यूएम-170 टोही ड्रोन मार गिराए और कब्जे में लिए। ईरान ने अन्य ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका पहले ऐसे कुछ दावों को खारिज कर चुका है। विडंबना यह है कि सैन्य हलचल के बीच कूटनीतिक संपर्क भी जारी हैं। होर्मुज में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए चिंता बढ़ा रहा है।

दैनिक विश्वनाथ समाचार
इंदौर, बुधवार 4 नवम्बर 2026

पीथमपुर के जल संकट का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मिले जनप्रतिनिधि

नर्मदा पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति बढ़ाने की मांग, औद्योगिक विस्तार और बढ़ती आबादी के लिहाज से वर्तमान व्यवस्था को बताया अपर्याप्त

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

पीथमपुर। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में लंबे समय से चली आ रही जल समस्या के स्थायी समाधान की मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। क्षेत्र में बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के बीच नर्मदा पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ाने की मांग उठाई गई है।

धार सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से सौजन्य भेंट कर पीथमपुर की जल समस्या से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि पीथमपुर मध्यप्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं और आवासीय क्षेत्रों में



भी पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था उद्योगों और आम नागरिकों दोनों की जरूरतों के लिहाज से अपर्याप्त साबित हो रही है। जनप्रतिनिधियों ने नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से पीथमपुर को मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग रखी, ताकि रहवासियों को राहत मिलने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को भी आवश्यक जल उपलब्ध हो सके।

टीही-धार रेलखंड पर दौड़ने को तैयार इलेक्ट्रिक ट्रेन, 47 किमी के ट्रैक पर विद्युतीकरण का काम पूरा

4 नवंबर को प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर करेंगे निरीक्षण और विद्युत इंजन का ट्रायल, 5-6 नवंबर को रेल संरक्षा आयुक्त करेंगे निरीक्षण

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

पीथमपुर। इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत टीही से धार के बीच रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

टीही-धार रेलखंड पर 25 केवी एसी विद्युतीकरण सहित सभी आवश्यक निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। दाहोद-इंदौर नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत टीही से धार तक नवनिर्मित सिंगल लाइन की कुल लंबाई 47.14 रूट किलोमीटर और 59.76 ट्रैक किलोमीटर है। इस रेलखंड में 2.957 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। रेलवे द्वारा 25 केवी एसी ओएचई, सुरंग निर्माण और सिग्नलिंग सहित अन्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं। निर्माण विभाग द्वारा 2 नवंबर को इलेक्ट्रिक इंजन चलाकर 130 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रैक क्षमता का परीक्षण भी किया जा चुका है। अब 4 नवंबर 2026 को पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रजनीश कुमार गोयल रेलखंड का निरीक्षण करेंगे और विद्युत इंजन का ट्रायल लिया जाएगा।

इसके बाद 5 और 6 नवंबर को रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिमी परिमंडल द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान इंजन को 120 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलाकर संरक्षा और परिचालन व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा।

त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई,

पीथमपुर में 5 फर्मों का निरीक्षण



अभिषेक खंडेलवाल
विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

मिठाई, नमकीन और खाद्य तेल सहित 15 नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे, सांवलिया रतलामी नमकीन में साफ-सफाई की कमी सहित मिलीं अनियमितताएं

पीथमपुर। त्योहारी सीजन में मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पीथमपुर स्थित पांच खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभिहित अधिकारी अनिता सिंगारे के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम गोपाल मऊटा एवं सुभाष खेड़कर की टीम ने पीथमपुर की छत्रछाया कॉलोनी स्थित फर्म सांवलिया रतलामी नमकीन का निरीक्षण किया।

यहां से सांवलिया रतलामी नमकीन सेव पैक, खुला मावा, पॉम तेल और मोतीचूर के लड्डू के नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की कमी पाई गई। इसके अलावा नमकीन निर्माण में उपयोग किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल से संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिले। इन कमियों को देखते हुए संबंधित फर्म को सुधार सूचना नोटिस जारी किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पीथमपुर में कुल पांच फर्मों



का निरीक्षण कर अलग-अलग खाद्य पदार्थों के 15 नमूने एकत्रित किए। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल की राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।

प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित स्थिति स्पष्ट होगी। विभाग के अनुसार, प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारी सीजन में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिठाई निर्माताओं, रेस्टोरेंट संचालकों और नमकीन निर्माताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेंगे।

औद्योगिक नगरी की सड़कों का दर्द लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किया स्वागत

बदहाल सड़कों की समस्या की ओर दिलाया ध्यान, लोकेश पथरिया सहित स्थानीय साथियों ने गर्मजोशी से किया अभिनंदन



अभिषेक खंडेलवाल
विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

पीथमपुर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीथमपुर आगमन पर स्थानीय साथियों एवं समर्थकों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने रखा गया। पीथमपुर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं और प्रतिदिन हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों, उद्यमियों एवं आम नागरिकों का आवागमन होता है।



इसके बावजूद क्षेत्र की कई सड़कों की खराब स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जगह-जगह गड्ढे और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आवागमन में दिक्कतों का असर औद्योगिक गतिविधियों के साथ आमजन के दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है। स्थानीय साथियों ने मंत्री विजयवर्गीय का स्वागत करते हुए कहा कि जिस पीथमपुर से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को गति मिलती है, वहां बेहतर सड़क और आवागमन की सुविधाएं होना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर लोकेश पथरिया, बलराम रघुवंशी, पीयूष मिश्रा, जयदेव धोते, रघुनाथ चावड़ा, बबलू श्रीवास्तव, कुंदन रघुवंशी, दीपू सिंह, हर्ष झबड़े, शिवम चौरसिया, उपेंद्र मिश्रा, प्रकाश शर्मा एवं वीरेंद्र रघुवंशी सहित अन्य इष्ट मित्र उपस्थित रहे।

जल कर नहीं दिया तो अब काट देंगे नल कनेक्शन

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

इंदौर। नगर निगम (Municipal council) द्वारा जल कर (water tax) की राशि नहीं चुकाने की नागरिकों में बढ़ती हुई आदत को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि जो नागरिक जल कर नहीं देंगे, उनका नल कनेक्शन काट (disconnected) दिया जाएगा। इसके साथ ही इन नागरिकों से बकाया जल कर की राशि की वसूली के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू की जाए।पानी के संकट के इस दौर में नगर निगम का ध्यान एक तरफ जहां पानी को बचाने और पानी की कमी की स्थिति को दूर करने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निगम की चिंता जल कर के रूप में मिलने वाली अत्यंत कम राशि को लेकर भी है।

पिछले तीन दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने पानी के काम की बैठक में समीक्षा की। इस बैठक में पानी लाने पर खर्च होने वाली राशि और जल कर के रूप में मिलने वाली राशि पर भी विचार किया गया।

तीनों सेक्टरों में धूल से रहवासी परेशान, हाउसिंग, सागौर और इंडोरामा में वाहनों के साथ हवा में फैलती धूल, जिम्मेदार विभागों की निगरानी पर सवाल

पीथमपुर की सड़कों से उठता धूल का गुबार, सांसों पर पड़ रहा असर



जीवन डोडिया
विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

औद्योगिक नगरी पीथमपुर में प्रदूषण की समस्या केवल फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है। शहर की सड़कों से उड़ती धूल भी अब रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।

पीथमपुर। हाउसिंग, सागौर और इंडोरामा सहित तीनों सेक्टरों में कई स्थानों पर सड़कों से उठने वाले धूल के गुबार लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। पीथमपुर एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहां दिनभर बड़ी संख्या में ट्रक, कंटेनर, डंपर और अन्य भारी वाहन गुजरते हैं।

कई सड़कों पर धूल जमा रहती है

जो वाहनों के निकलते ही हवा में फैल जाती है। सड़क किनारे रहने वाले परिवारों, दुकानदारों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को इसका सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर धूल इतनी अधिक उड़ती है कि कुछ समय के लिए आसपास



का वातावरण धुंधला हो जाता है।

बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता

सड़कों से उड़ने वाली धूल का सबसे अधिक सामना बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को करना पड़ सकता है। घरों में धूल पहुंचने से सफाई की समस्या भी बनी रहती है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क से गुजरते भारी वाहनों के कारण दुकानों और सामान पर धूल की परत जम जाती है। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को धूल के कारण सामने देखने में परेशानी होती है।

औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें भी बन रहीं परेशानी की वजह

पीथमपुर में औद्योगिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव भी अधिक रहता है। यदि सड़कें क्षतिग्रस्त हों या उन पर नियमित सफाई और धूल नियंत्रण की व्यवस्था न हो, तो वाहनों की आवाजाही के साथ धूल का गुबार उठना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है।

जिम्मेदार विभाग कब लेंगे सुध

हाउसिंग, सागौर और इंडोरामा सहित तीनों सेक्टरों के रहवासियों को सड़क से उड़ती धूल से राहत दिलाने के लिए नियमित सफाई, आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और भारी वाहनों से प्रभावित मार्गों पर धूल नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम जरूरी हैं। नगर पालिका, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े संबंधित विभागों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इस समस्या की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। पीथमपुर को प्रदेश की औद्योगिक पहचान बनाने में यहां के उद्योगों की बड़ी भूमिका है, लेकिन औद्योगिक विकास के साथ नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर सड़कें भी उतनी ही जरूरी हैं।

घायल आरक्षक ने साहस दिखाकर काबू किया

खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे युवक ने पुलिसकर्मी पर किया चाकू से हमला

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र में खुद को कमरे में बंद कर चाकू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे युवक को काबू करने के दौरान आरक्षक घायल हो गया।

पुलिस की सूझबूझ से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया

जानकारी के मुताबिक



1 नवंबर 2026 की रात करीब 11 बजे डायल-100 पर सूचना मिली कि भुसामंडी रोड पर एक युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और चाकू से खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर एफआरवी-30 मौके पर पहुंची। गश्त कर रहे थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल और आरक्षक राजपाल सैंधव भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कमरे में जितेंद्र रघुवंशी पिता सुरेंद्र रघुवंशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी रायसेन अपनी बहन के साथ मौजूद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और करीब आधे घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान चाकू लेने के प्रयास में युवक ने अचानक आरक्षक राजपाल सैंधव की पीठ पर वार कर दिया। घायल होने के बावजूद आरक्षक ने हिम्मत नहीं हारी और थाना प्रभारी व साथियों के सहयोग से युवक को काबू कर चाकू छीन लिया। घायल आरक्षक को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पीठ पर तीन टांके लगे हैं।

फिलहाल उनकी हालत ठीक है। युवक जितेंद्र को उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार जारी है।

जिले में हथियार लेकर चलने, बिना अनुमति सभा-रैली और डीजे पर रोक, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी प्रतिबंधित

कलेक्टर ने धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड लेकर नहीं चलेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति किसी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। डीजे, बैंड और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत रोक रहेगी। धरना-प्रदर्शन में एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ और पटाखे-विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति टेंट, पंडाल का निर्माण, सड़क-हाइवे पर एकत्र होकर यातायात में व्यवधान करना भी प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया पर दल, धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति विरोधी तथा भावनाएं भड़काने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, पोस्ट अपलोड करने पर भी रोक लगाई गई है। ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों में बिना अनुमति शूटिंग, वीडियो और रील बनाना प्रतिबंधित रहेगा। होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों और मकान मालिकों को बाहरी व्यक्तियों व किरायेदारों की सूचना प्रतिदिन संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश 3 नवंबर से आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।

दैनिक विश्वनाथ समाचार
इंदौर, बुधवार 4 नवम्बर 2026

शेयर बाजार में निवेशक पर चौतरफा शुल्क!

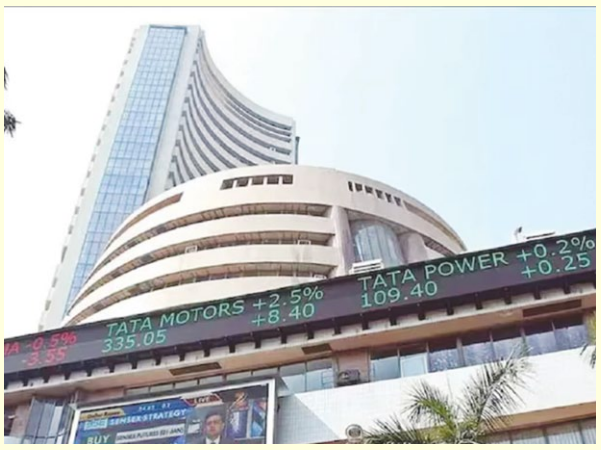
खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, मुनाफे पर अलग कर

सम्पादकीय- विदेशी निवेशकों की चिंता पर कर समीक्षा की चर्चा, लेकिन छोटे निवेशक के खाते से कटने वाली रकम और उसे मिलने वाली सुरक्षा पर बड़ा सवाल

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

शेयर बाजार में आम आदमी अपनी बचत लगाकर भविष्य संवारने की उम्मीद करता है, लेकिन निवेश करते ही उसके खर्च शुरू हो जाते हैं। शेयर खरीदने पर शुल्क, बेचने पर शुल्क और मुनाफा होने पर पूंजीगत लाभ कर। बाजार गिरने पर नुकसान निवेशक का, मगर लेनदेन की लागत अपनी जगह बनी रहती है। शेयरों की डिलीवरी खरीद पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.10 प्रतिशत और बिक्री पर भी 0.10 प्रतिशत है। यानी एक लाख रुपये की खरीद पर 100 रुपये और एक लाख रुपये की बिक्री पर 100 रुपये एसटीटी। इसके अतिरिक्त खरीद पर 0.015 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क, दलाली, विनिमय शुल्क और लागू वस्तु एवं सेवा कर जैसे खर्च भी हो सकते हैं। वास्तविक लागत सौदे और दलाल की दर पर निर्भर करती है। शेयर बाजार में एक साल से अधिक रखे गए पात्र सूचीबद्ध शेयरों पर सालाना कुल 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर है। 12 महीने या उससे कम रखने पर पात्र अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगता है। लागू उपकर अलग हो सकता है। यानी मुनाफे की सीमा पार होने पर कर की गणना भी निवेशक की कमाई घटाती है।

उधर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भारी



बिकवाली के बीच पूंजीगत लाभ कर और एसटीटी की समीक्षा की मांग तेज हुई है। 2026 में विदेशी निवेश की निकासी ने बाजार की चिंता बढ़ाई है। एसबीआई रिसर्च ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने का सुझाव दिया है, लेकिन यह सरकारी फैसला नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल

विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अगर कर राहत पर विचार हो सकता है, तो देश के छोटे निवेशक को पारदर्शी शुल्क, निष्पक्ष नियम और ठोस सुरक्षा क्यों नहीं? हर खरीद-बिक्री पर वसूली का हिसाब और निवेशक को मिलने वाले लाभ का हिसाब भी जनता के सामने होना चाहिए।

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से भड़के पप्पू यादव, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में दी शिकायत

बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। भगवान श्रीकृष्ण पर की गई कथित टिप्पणी से नाराज सांसद पप्पू यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव सोमवार को दिल्ली के पार्लियामेंट थाने पहुंचे और धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कथावाचक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया था। भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से नाराज हुए पप्पू यादव- पप्पू यादव ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए उन्हें सत्ता संरक्षित कथावाचक बताया और कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर रहेंगे। सांसद ने अपनी पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि कथावाचक अब अपने बयान को लेकर माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होने तक वह पीछे नहीं हटेंगे।



मतदाता सूची में सुधार पर सियासी घमासान

घुसपैठियों के नाम हटाने के मुद्दे पर आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष

दिल्ली में विपक्ष की रैली के ठीक अगले दिन हैदराबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। शाह के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक और तथ्यात्मक जवाब देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वहीं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआइआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

दरअसल, एसआइआर के तहत मतदाता सूची के मसौदे से करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष इसे वोट चोरी से जोड़कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। उसका आरोप है कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर वास्तविक मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर, सत्तापक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मृत, स्थानांतरित



और दोहरी प्रविष्टियों वाले नामों को हटाना जरूरी है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी का मताधिकार छीनना नहीं, बल्कि चुनाव व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

गृहमंत्री अमित शाह ने हटाए गए नामों के पीछे अलग-अलग कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें करीब 6.30 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं।

लगभग 2.80 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। इसके अलावा करीब तीन करोड़ ऐसे लोगों का भी उल्लेख किया गया, जो सत्यापन के दौरान अपने दर्ज पते पर उपलब्ध नहीं मिले। शाह ने इन लोगों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए अवैध घुसपैठ की आशंका जताई और कहा कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, केवल सत्यापन के दौरान किसी व्यक्ति का घर पर नहीं मिलना अपने आप में उसके विदेशी नागरिक या घुसपैठिया होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए अलग से तथ्यात्मक जांच और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है।

इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू देश में अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मुद्दा भी है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में बांग्लादेश से अवैध प्रवास को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस होती रही है। भाजपा का आरोप रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी हितों के लिए अवैध प्रवासियों को संरक्षण दिया और उन्हें पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल करने में मदद पहुंचाई। हालांकि, इन आरोपों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और किसी व्यक्ति को केवल संदेह या पते पर अनुपस्थित रहने के आधार पर घुसपैठिया घोषित नहीं किया जा सकता। भाजपा का यह भी कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होना चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता के लिए गंभीर चुनौती है। पार्टी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता का वैध आधार नहीं है, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं विपक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम भी हटने की आशंका है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह प्रत्येक मामले का निष्पक्ष सत्यापन करे और किसी भी पात्र नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित न होने दे।

कलेक्टर से हाट बाजार-मंनोरजन स्थल के लिए स्वीकृत

शासकीय जमीन पर बना दिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स...

आईटीआई कार्यकर्ता भाटिया ने जनसुनवाई में कलेक्टर को की शिकायत...

10 से अधिक दुकानो की नीलामी, कहीं हॉल तो कहीं दुकानें बेचने का दावा

बड़वाह - सरकारी जमीन किस काम के लिए आवंटित हुई और उसका इस्तेमाल किस काम में कर दिया गया...?

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

उक्त जमीन तत्कालीन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा हाट बाजार और मनोरंजन स्थल के लिए स्वीकृत की गई थी। लेकिन नगर पालिका बड़वाह के जिम्मेदारों ने वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। दुकानें बनीं तो उनकी नीलामी भी कर दी गई। अब सवाल यह कि क्या नगर पालिका ने कलेक्टर के आदेश को महज कागज का टुकड़ा समझा....?

बड़वाह। बड़वाह नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ कुलदीप किंशुक की कार्यशैली पर आईटीआई कार्यकर्ता हरभजनसिंह भाटिया उर्फ पिंकी बाबा ने ऐसा ही गंभीर मामला उठाया है। मंगलवार को खरगोन कलेक्टर में होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष दस्तावेजों और फोटोग्राफ्स के साथ शिकायत पहुंची। शिकायत में सरकारी जमीन पर आवंटन की शर्तों के विपरीत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने, दुकानों की नीलामी करने, शासकीय निर्माण अनुमतियां नहीं लेने और भू-भाटक जमा नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता श्री भटिया ने पूरे मामले में जांच करने और निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जमीन मिली हाट बाजार के लिए, बन गया कारोबार का ठिकाना

शिकायत के मुताबिक, कलेक्टर ने 19 दिसंबर 2024 को प्रकरण क्रमांक 150/अ-20 (3)/24-25 के तहत ग्राम बड़वाह के खसरा नंबर 168 की कुल 15.135 हेक्टेयर भूमि में से 191.4 वर्गमीटर जमीन नगर पालिका को हाट बाजार एवं मनोरंजन स्थल के लिए आवंटित



की थी। आवंटन आदेश की कंडिका-3 में साफ शर्त थी कि जमीन का उपयोग केवल आदेश में उल्लेखित प्रयोजन के लिए होगा। दूसरे प्रयोजन में इस्तेमाल होने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और जमीन राजस्व विभाग द्वारा वापस ली जाएगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस स्पष्ट शर्त के बावजूद नगर पालिका ने एमजी रोड स्थित शासकीय जमीन पर स्थापित स्कूल को तोड़कर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया। तल मंजिल की पांच और प्रथम मंजिल की पांच दुकानों की नीलामी भी कर दी गई। यानी जिस जमीन पर हाट बाजार और मनोरंजन स्थल होना था, वहां कथित तौर पर दुकानें बेचकर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं।

दूसरी जमीन पर भी वही खेल

मामला केवल एक भूखंड तक सीमित नहीं है। शिकायत में दूसरे आवंटन का भी उल्लेख है। प्रकरण क्रमांक 151/अ-20 (3)/24-25 में 19 दिसंबर 2024 को ही खसरा नंबर 168 से 269.7 वर्ग मीटर भूमि नगर पालिका को हाट बाजार एवं मनोरंजन स्थल के लिए आवंटित की गई थी। इस जमीन पर भी वही शर्त लागू थी. उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त होकर जमीन राजस्व विभाग को वापस जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस जमीन पर भी दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। तल मंजिल की करीब आठ दुकानों और प्रथम मंजिल के हॉल की नीलामी तक कर दी गई। शिकायत के साथ दुकान बिक्री के टेंडर, रसीदें और कॉम्प्लेक्स के फोटो भी संलग्न किए गए हैं। अब सवाल यह है कि जब जमीन का आवंटन हाट बाजार के लिए था, तो स्थायी व्यावसायिक निर्माण और दुकानें बेचने की अनुमति किसने दी...?

मुख्य चौराहे पर भी निर्माण को लेकर उठाए सवाल

शिकायत में बड़वाह के मुख्य चौराहे, इंदौर रोड स्थित गौरव विजयवर्गीय की दुकान से लेकर जयंती स्वीट्स की दुकान तक करीब 12 दुकानों के तल पर निर्माण का मामला भी उठाया गया है।शिकायतकर्ता के अनुसार, इन दुकानों के ऊपर नगर पालिका द्वारा प्रथम मंजिल पर दुकानें बनाई जा रही हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में नगर पालिका ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4560, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 में कहा है कि फेस-1 की उक्त दुकानों का निर्माण निकाय द्वारा नहीं करवाया गया है। इसी जवाब को आधार बनाकर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब नगर पालिका ने नीचे की दुकानों का निर्माण नहीं किया, तो उनके ऊपर प्रथम मंजिल पर दुकानें बनाने का अधिकार उसे किसने दिया....? आरोप यह भी है कि इस निर्माण के लिए जरूरी शासकीय अनुमतियां और टीएंडसीपी की मंजूरी भी नहीं ली गई। प्रथम मंजिल की कुछ दुकानों की नीलामी किए जाने की आशंका भी शिकायत में जताई गई है।

भू-भाटक जमा नहीं, अनुमतियां के भी ठिकाने नही

श्री भाटिया ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर द्वारा आवंटित जमीनों का भू-भाटक नगर पालिका ने जमा नहीं किया है। वहीं, दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए टीएंडसीपी कार्यालय से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई है। शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल नियम विरुद्ध निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी जमीन के आवंटन की शर्तों की अनदेखी और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला होगा।

दुकान खरीदने वालों का पैसा कौन लौटाएगा...?

आईटीआई कार्यकर्ता हरभजनसिंह भाटिया ने कलेक्टर से मांग की है कि आवंटन की शर्तों के विपरीत बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण तत्काल रोका जाए। दुकानों के खरीददारों की राशि वापस दिलाई जाए और जमीन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह आवंटित की गई थी। साथ ही मुख्य चौराहे पर दुकानों के ऊपर किए जा रहे निर्माण की जांच, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है।उल्लेखनीय है कि इस मामले में नपा सीएमओ कुलदीप किंशुक का कहना है नपा परिषद के निर्णय अनुसार ही हमारे विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं।

हेलीपैड, टेंट सिटी और हिंगलाज रिसोर्ट का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रदेश कैबिनेट की गांधी सागर में प्रस्तावित बैठक की तैयारियां प्रारंभ, कलेक्टर सहित अधिकारी पहुंचे गांधी सागर

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

तुलसीराम राठौर

मंदसौर नाहरगढ़। मध्यप्रदेश कैबिनेट की जिले के गांधी सागर में प्रस्तावित आगामी कैबिनेट बैठक की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। तैयारियों के सिलसिले में कलेक्टर दिव्यांक सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन सहित जिलाधिकारी मंगलवार दोपहर गांधी सागर पहुंचे। कलेक्टर ने विभिन्न स्थलों पर तैयारियों का जायजा लिया।



इस दौरान हेलीपैड, टेंट सिटी तथा हिंगलाज रिसोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं के संबंध में विचार-विमर्श किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सेंट मैरीज़ हॉस्पिटल बेटमा में विशेष परामर्श शिविर 15 नवंबर को

बेटमा। नगर के देपालपुर रोड़ स्थित सेंट मैरीज़ हॉस्पिटल में 15 नवंबर 2026, रविवार को विशेष परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। शिविर में यूरोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. शर्विल थत्ते एमएस, एमसीएच (यूरोलॉजी) मूत्र एवं पुरुष रोग विशेषज्ञ तथा डॉ. सरगम जायसवाल एमबीबीएस, एमडी (चर्म रोग विशेषज्ञ) त्वचा, गुप्त एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ के रूप में परामर्श देंगी। शिविर में पथरी, पेशाब संक्रमण, किडनी ऑपरेशन, प्रोस्टेट, मूत्र संबंधी विकारों तथा कील-मुंहासे, एलर्जी, एक्जिमा, सोरायसिस, फंगल इन्फेक्शन, सफेद दाग, बालों की समस्या और मस्से आदि रोगों का विशेष परामर्श उपलब्ध रहेगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार शिविर के दौरान लेब, सोनोग्राफी और एक्स-रे जांच किफायती दरों पर की जाएगी।



दैनिक विश्वनाथ समाचार
इंदौर, बुधवार 4 नवम्बर 2026

मिट्टी के दीये बनने शुरू

महंगाई की मार के बीच कुम्हारों को बाजार से उम्मीद

इलेक्ट्रॉनिक दीयों और सजावटी लाइटों ने बढ़ाई पारंपरिक दीयों की चुनौती, चाक पर दिन-रात जुटे कुम्हार

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

पीथमपुर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों को रोशन करने की तैयारियों के बीच मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हार भी अपने काम में जुट गए हैं। कहीं चाक पर मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं तैयार दीयों को धूप में सुखाया जा रहा है। दीपावली से पहले कुम्हारों के घरों और कामकाज के स्थानों पर मिट्टी के दीये तैयार करने का काम शुरू हो गया है। छोटे, बड़े, सामान्य और सजावटी दीयों के साथ पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले मिट्टी के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। कुम्हार परिवारों के सदस्य इस काम में जुटे हैं, ताकि त्योहार के समय बाजार में मांग के अनुसार दीयों की आपूर्ति की जा सके। कुम्हार परिवारों के लिए दीपावली का त्योहार साल की सबसे महत्वपूर्ण कमाई का अवसर होता है।



महंगाई ने बढ़ाई लागत, मुनाफे पर असर

कुम्हारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी कच्चे माल, मिट्टी, ईंधन, रंग और परिवहन सहित अन्य खर्चों में बढ़ोतरी की है। दीये बनाने में मेहनत भी अधिक लगती है, लेकिन बाजार में ग्राहकों की कीमत को लेकर अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में लागत बढ़ने के बावजूद उचित दाम मिलना आसान नहीं रहता। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली के दौरान लोग पारंपरिक मिट्टी के दीयों को प्राथमिकता देंगे, जिससे उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा।

इलेक्ट्रॉनिक दीयों ने बदला बाजार का रुख

पिछले कुछ वर्षों में बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दीये, बैटरी से चलने वाली लाइटें, झालर और रंग-बिरंगी सजावटी लाइटों की मांग बढ़ी है। ये उत्पाद लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें जलाने के लिए तेल या बाती की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण कई लोग पारंपरिक मिट्टी के दीयों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक विकल्प खरीदने लगे हैं। इसका असर पारंपरिक दीये बनाने वाले कुम्हारों के कारोबार पर भी पड़ रहा है।

परंपरा को बचाने की अपील

मिट्टी के दीये केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दीपावली की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुम्हारों की आजीविका भी इसी परंपरा से जुड़ी हुई है। ऐसे में मिट्टी के दीये खरीदना स्थानीय कारीगरों और उनके परिवारों की मेहनत को प्रोत्साहन देने का माध्यम भी है। दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सजावट के साथ मिट्टी के दीयों का महत्व आज भी बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस बार पीथमपुर के बाजार में पारंपरिक दीयों की कितनी मांग रहती है और कुम्हारों को त्योहार से कितनी राहत मिलती है।

हिंगोट युद्ध को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक

शराब पीकर आने वाले योद्धाओं को नहीं मिलेगा प्रवेश, मैदान में लगेंगी लोहे की जालियां

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

गौतमपुरा। दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होने वाले ऐतिहासिक हिंगोट युद्ध को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को गौतमपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में सुरक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडिशनल एसपी राजकृष्ण, एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा एवं एसडीओपी संघप्रिय सम्राट ने की। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप सिंह, सीएमओ मयूरी वर्मा, बीएमओ विभा नागर, डॉ. सुनील असाटी, सुपरवाइजर प्रवीण झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गगन बाहेती, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रमोद सक्सेना, उपाध्यक्ष राजा पाटीदार, कांग्रेस नेता मोहन चौधरी, देवकरण गुर्जर, जगदीश भावसार, चेतन भावसार, सुनील जोशी, पार्षद अब्बू भाटी, नगर सुरक्षा समिति अध्यक्ष कंवरलाल नामदेव सहित जनप्रतिनिधि, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।



सुरक्षा को लेकर सख्त फैसले

बैठक में तय किया गया कि शराब पीकर आने वाले योद्धाओं को युद्ध मैदान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शकों की सुरक्षा के लिए नगर परिषद द्वारा मैदान में लोहे की मजबूत जालियां लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की तीन टीमें मैदान में तैनात रहेंगी, ताकि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके। बिजली विभाग की दो टीमें रोशनी और विद्युत व्यवस्था की निगरानी करेंगी। गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध सदियों पुरानी लोक परंपरा और साहस का प्रतीक है। पड़वा पर कलंगी और तुर्रा दलों के योद्धा जलते हिंगोट रूपी अग्निबाणों से सामना करते हैं। इसे देखने हजारों दर्शक पहुंचते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

भ्रष्ट अफसरों की सूचना देने के लिए लोकायुक्त ने 8 जिलों में टांगे30 बोर्ड

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

इंदौर। भ्रष्ट अफसरों (corrupt officials) के खिलाफ लोकायुक्त (Lokayukta) पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा था कि कई जिलों में लोग लोकायुक्त पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हर जिले में चार-पांच सरकारी आफिस में बोर्ड (board) टांगे हैं, जिसमें लोकायुक्त का नंबर भी दर्ज है। लोकायुक्त पुलिस इस साल 40 से अधिक भ्रष्ट अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ चुकी है। वहीं 5 अफसरों के यहां छापे की कार्रवाई कर उनकी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया गया है। लेकिन फिर भी लोकायुक्त पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कई लोग लोकायुक्त पुलिस की जानकारी नहीं होने से उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं।

इसके चलते कई भ्रष्ट अफसर बच जाते हैं। डीसीपी आनंद चौहान ने बताया कि इसके चलते लोकायुक्त पुलिस ने अब आलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, धार सहित आठ जिलों में चार से पांच बोर्ड लगाए हैं। ये बोर्ड यांत्रिकी विभाग, जिला पंचायत, नगर परिषद, जनपद पंचायत, एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में लगाए गए हैं। इस पर लोकायुक्त का नंबर है और लोगों से कहा गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो नंबर पर संपर्क करें।

इंदौर में स्थापना दिवस समारोह पर सियासी हलचल

मंत्री विजयवर्गीय पहुंचे लेकिन आठ विधायक रहे नदारद

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

इंदौर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर में आयोजित समारोह अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। एक नवंबर को लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी तो रही, लेकिन शहर के आठ विधायक समारोह में शामिल नहीं हुए।

खास बात यह रही कि

कार्यक्रम के मंच पर विधायकों के नाम से कुर्सियां आरक्षित की गई थीं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में उन कुर्सियों पर अधिकारी बैठे दिखाई दिए। इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इसे भाजपा के भीतर आपसी तालमेल की कमी से जोड़कर निशाना साधा है, जबकि भाजपा ने विधायकों की व्यस्तता को उनकी गैरमौजूदगी की वजह बताया है। दरअसल, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी कड़ी में इंदौर के लता मंगेशकर सभागृह में भी विशेष समारोह रखा गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से शहर के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। मंच पर उनके बैठने के लिए बाकायदा नाम के साथ कुर्सियां लगाई गई थीं। हालांकि, कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी आठों विधायक समारोह में नहीं पहुंचे।



राजनीतिक बहस का कारण बन गया है

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति

»» कई सवाल उठ रहे हैं। स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में शहर के विधायकों की एक साथ गैरमौजूदगी को सामान्य घटनाक्रम मानने के बजाय राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। खासकर तब, जब मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई थी। समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों ने भी इस स्थिति पर सवाल उठाए। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या विधायकों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी या फिर किसी अन्य कारण से वे इसमें शामिल नहीं हो सके। विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में शहर के आठ विधायकों का नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है।

पार्टी का मानना है कि जब किसी बड़े सरकारी आयोजन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है, तो उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का अनुपस्थित रहना राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है।

भाजपा ने दी सफाई, कहा- अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं विधायक

दूसरी ओर, भाजपा ने इस मामले को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी या आपसी नाराजगी की संभावना से इनकार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि विधायक और जनप्रतिनिधि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के समाधान और अन्य जरूरी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। संभव है कि इसी व्यस्तता के चलते वे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर किसी तरह की अनबन नहीं है और सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में एकजुट होकर काम कर रहे हैं।

अधिकारियों के बैठने से बढ़ी चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा मंच पर विधायकों के नाम से आरक्षित कुर्सियों पर अधिकारियों के बैठने को लेकर हो रही है। आमतौर पर स्थापना दिवस जैसे सरकारी समारोहों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे आयोजनों में जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था भी की जाती है।

24 साल देश सेवा के बाद गृह नगर लौटे मेजर मनोहर, देपालपुर में निकला भव्य चल समारोह

शहीद भागीरथ सिलावट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन, नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर किया आत्मीय स्वागत

विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

विशाल चांदना

देपालपुर। देश की सुरक्षा और सेवा में अपने जीवन के 24 वर्ष समर्पित करने के बाद सीआरपीएफ में सेवाकाल पूर्ण कर मेजर मनोहर के गृह क्षेत्र लौटने पर देपालपुर नगर एवं उनके गृह ग्राम भिड़ोता में हर्ष और उत्साह का माहौल रहा। उनके नगर आगमन पर नागरिकों ने आत्मीय स्वागत करते हुए भव्य चल समारोह निकाला। चल समारोह के दौरान मेजर मनोहर ने शहीद भागीरथ सिलावट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद नगर के विभिन्न मार्गों से निकले चल समारोह में बड़ी संख्या में नागरिक, युवा एवं गणमान्यजन शामिल हुए। जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया। मेजर मनोहर के स्वागत में नगरवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। विशेष बात यह रही कि जैसे ही चल समारोह नगर में निकला, मौसम ने भी करवट ली और बारिश होने लगी। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और स्वागत का सिलसिला जारी रहा। मेजर मनोहर ने अपने जीवन के 24 वर्ष देश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित किए। उनकी इस लंबी सेवा यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों ने गर्व व्यक्त किया। देपालपुर नगर के साथ ही उनके गृह ग्राम भिड़ोता में भी भव्य स्वागत किया गया। देश सेवा का दायित्व निभाकर अपने क्षेत्र में लौटे मेजर मनोहर का सम्मान समारोह नगरवासियों के लिए गौरव और भावुकता का अवसर बन गया।





दैनिक
विश्वनाथ समाचार
इंदौर, बुधवार 4 नवम्बर 2026

पांच बीघा में किसानों ने शुरू किया प्रयोग, प्रति बीघा 25 से 30 क्विंटल उत्पादन की उम्मीद;

सफल रहा तो अगले वर्ष 100 बीघा तक होगा विस्तार

कम पानी में लहसुन की खेती का नया प्रयोग, बेड-मल्चिंग तकनीक से उत्पादन बढ़ाने की तैयारी



संदीप सेन-9755161156
विश्वनाथ समाचार
www.vishwanathsamachar.com

कम बारिश, सिंचाई के पानी की कमी और खेती की बढ़ती लागत के बीच किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इंदौर। इसी कड़ी में इंदौर जिले के देपालपुर इलाके के बनेड़िया गांव के किसानों ने बेड एवं मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती का प्रयोग शुरू किया है। फिलहाल करीब 5 से 10 बीघा क्षेत्र में किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं। किसानों को कम पानी में बेहतर नमी, गुणवत्तापूर्ण फसल और अधिक उत्पादन की उम्मीद है। प्रयोग के परिणाम अनुकूल रहे तो अगले वर्ष इसका रकबा बढ़ाकर करीब 100 बीघा तक ले जाने तथा प्याज की खेती में भी इस तकनीक को अपनाने की योजना है।

प्रति बीघा 20 से 22 हजार रुपए शुरुआती खर्च

किसानों के अनुसार बेड तैयार करने, मल्चिंग और अन्य शुरुआती कार्यों पर प्रति बीघा करीब 20 से 22 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं।

शुरुआती लागत

अधिक होने के बावजूद किसान इसे पानी की बचत और बेहतर उत्पादन की संभावना के रूप में देख रहे हैं। पारंपरिक विधि से प्रति बीघा 18 से 20 क्विंटल उत्पादन की तुलना में बेड विधि से 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक परिणाम कटाई के बाद ही सामने आएंगे।

शुरुआती दौर में नमी बनाए रखना जरूरी

किसान बाबूलाल पटेल एवं नितिन पटेल ने बताया कि बेड विधि से लहसुन लगाने के शुरुआती चरण में खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए पहले बेड में अच्छी तरह सिंचाई की जाती है, इसके बाद लहसुन की चुपाई की जाती है। मल्चिंग से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। मौसम और मिट्टी की स्थिति अनुकूल रहने पर करीब दो घंटे की सिंचाई के बाद 10 से 12 दिनों तक नमी बनी रह सकती है। इससे आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग और अनावश्यक बर्बादी कम करने में मदद मिल सकती है।

40 प्रतिशत तक पानी बचने की संभावना

किसान लाखन सिंह दरबार ने बताया कि बेड एवं मल्चिंग विधि में पारंपरिक खेती की तुलना में करीब 40 प्रतिशत तक पानी की बचत होने की संभावना है। इस पद्धति में मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ बेड निर्माण से वायु संचार भी बेहतर होने की उम्मीद है। उचित प्रबंधन से उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है, हालांकि इसके लिए वास्तविक परिणामों का आकलन जरूरी होगा।



कुछ स्थानों पर दोबारा करनी पड़ी चुपाई

किसान नितिन पटेल ने बताया कि लहसुन की फसल लगाए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर अंकुरण नहीं होने से खाली जगहों पर मजदूरों के माध्यम से दोबारा चुपाई कराई जा रही है। इससे अतिरिक्त खर्च और मेहनत लग रही है। वहीं बेड के बीच खाली स्थानों पर राजमा की फसल भी लगाई गई है, जिसके पौधे अब अंकुरित होकर पत्तियां निकालने लगे हैं। क्षेत्र में इस तरह की खेती को देखने के लिए आसपास के गांवों के किसान भी खेतों पर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को मांगीलाल भगत एवं देवेंद्र भगत ने भी खेत पहुंचकर फसल का जायजा लिया।





कृषि विस्तार अधिकारी ने किया निरीक्षण

मंगलवार को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनम तिवारी ने भी खेत का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से खेती की तकनीक, शुरुआती लागत, सिंचाई और फसल की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक कृषि संबंधी मार्गदर्शन दिया।

सफलता मिली तो लहसुन के बाद प्याज में भी प्रयोग

किसानों का कहना है कि इस वर्ष फसल की बढ़वार, उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार भाव और कुल लागत के आधार पर तकनीक की सफलता का आकलन किया जाएगा।

परिणाम संतोषजनक रहे

अगले वर्ष करीब 100 बीघा क्षेत्र में बेड-मल्चिंग विधि से खेती करने का प्रयास होगा। इसके साथ ही प्याज की खेती में भी इस तकनीक को अपनाने की तैयारी है। किसानों को उम्मीद है कि आधुनिक पद्धति से कम पानी में बेहतर फसल तैयार कर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक संदीप परमार द्वारा उदयरत्न ऑफसेट 170/2, दारू गोडाउन के आगे, आगर रोड, उज्जैन से मुद्रित एवं 215, सोमानी नगर, एयरपोर्ट 60 फीट रोड, इंदौर (म.प्र.) 452005 से प्रकाशित।
सनातन दवदी (स्थानीय संपादक)/ उत्कर्ष जैन-(जीवन डोडिया-9926084685) RNI No. MPHIN/25/A4357- (सभी विवादों का क्षेत्र इंदौर रहेगा)- (नोट : पी.आर.बी. एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)-मो. 7000928755 E-mail:- vishwanathsamachar@gmail.com